

सी. राममनोहर रेड्डी, (2021), *इंडिया एंड द पैंडेमिक: द फ़र्स्ट इयर, नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान, पृष्ठ 335, मूल्य ₹695, ISBN: 978-93-5442-009-2*

इंडिया एंड द पैंडेमिक: द फ़र्स्ट इयर नामक पुस्तक में प्रस्तुत अध्याय सर्वप्रथम 'भारतीय मंच' में प्रकाशित किए गए थे। पुस्तक में 24 अध्याय हैं और सभी कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। पुस्तक को कोविड-19 के विभिन्न विषयगत पहलुओं से संबंधित आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड-1 में थॉमस इब्राहिम और के. सुजाता राव इस सवाल से मुखातिर रहे कि क्या देश में वायरस के फैलाव को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। देश भर में लॉकडाउन सफलता की कहानी नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन की तैयारी नहीं की गई थी। इस दौरान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग भी नजर नहीं आया।

भारत के इतिहास में महामारी से संबंधित खंड-2 दक्षिण एशिया में महामारियों के पिछले अनुभवों को दर्शाता है। महामारियों ने किस तरह राज्य और समाज दोनों का पुनर्गठन किया। सन् 1897 के बंबई में प्लेग के प्रकोप को प्रतीक चक्रवर्ती ने लिखा कि औपनिवेशिक राज्य के लिए आपातकालीन शक्तियों को एकत्र करने के लिए मंच निर्धारित किया, और शहरी स्थानों को फिर से व्यवस्थित करने और संदिग्ध निकायों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग किया गया। चक्रवर्ती बताते हैं कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति के विषयों और नागरिकों पर अधिक सरकारी नियंत्रण और निगरानी की घटनाएँ घटित होती हैं।

शीतल छाबरिया ने अपने अध्याय में 1897 की बॉम्बे प्लेग महामारी की शैली की पृष्ठताछ की है। वह बताती हैं कि अगर हम प्लेग को रोगजनक प्रकरण के रूप में नहीं, बल्कि गरीबी के परिणाम के रूप में देखते हैं, और औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता के कम प्रावधान के रूप में देखते हैं तो उसके लिए क्या सबक लिए जा सकते हैं। 1898 के प्लेग के तहत कलकत्ता के अनुभवों पर प्रेरणा अग्रवाल का अध्याय, राज्य और कारखानों और मिल मालिकों की बात करता है। हरीश नारायणदास ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में चेचक को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की लगभग असंभव कहानी की पड़ताल की है। उनका तर्क है कि भारत में, जहां रोग स्थानिक था, स्थानीय समुदायों के साथ टीका लगाने वालों के सहयोग ने मिशन को 'पॉक्स' के खिलाफ एक सामूहिक और सफल प्रतिरोध बना दिया।

खंड-3 में, 'कोविड-19: प्रारंभिक प्रभाव' अध्याय में महामारी के प्रसार को प्रारंभिक चरण के दौरान लिखा गया है। दोनों स्वास्थ्य और आजीविका के मुद्दों से निपटते हैं; दोनों इस बात से इनकार

करते हैं कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था/आजीविका के बीच व्यापार निरस्त है। विक्रम पटेल ने अन्य बातों के साथ-साथ उन लोगों के स्वास्थ्य के विनाशकारी प्रभाव की चेतावनी दी जो लॉकडाउन से पहले खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थे और उन्हें देखभाल नहीं मिल सकी, और जिन लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। आनंद लाल राय और मैत्रेश घटक ने सार्वजनिक और अर्थव्यवस्था दोनों में लघु और दीर्घकालिक हस्तक्षेपों के लिए एक विस्तृत विकल्प की पेशकश के साथ ही दोनों को अलग-अलग देखने के बजाय जोड़ कर देखा।

खंड-4, कानून, न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े पहलुओं को संबोधित करता है। उपेंद्र बक्शी ने तर्क दिया है कि संविधानवाद ने अदालतों को उजाड़ दिया है, खासकर उन कामगारों के अधिकारों के अभ्यास के मामले में, जिसने उन्हें सड़कों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। प्रतीक्षा बक्शी और नवशरण सिंह, महामारी के दौरान सभी महिला कैदियों की रिहाई का आग्रह करते हैं। हर्ष मंडेर ने अप्रैल 2020 में दायर पहली याचिकाओं में से एक की कहानी को फिर से समेटा है, जिसमें प्रवासी कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

खंड-5 में नौकरियों, आजीविका और भूख तथा विस्तारित लॉकडाउन के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देबराज रे, एस. सुब्रमण्यन और लोर वैडेवॉल एक ऐसी नीति के खिलाफ बहस करते हैं, जिसने आजीविका के लिए हुई तबाही को नजरअंदाज कर दिया है। प्रवासी कामगारों के बीच नौकरियों और उपभोग पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल पर राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों का अध्ययन करके माजिद एक अनुमान बताते हैं कि कामगार कमजोर अवस्था में होते हैं। एक उद्योग की केस स्टडी में गायत्री नायर स्थानिक के दौरान भारत की टमटम अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की अनूठी असुरक्षा के बारे में लिखती हैं।

मैक्रो इकोनॉमी, खंड-6 का विषय है। यहां आर. नागराज का तर्क है कि महामारी की मार से पहले से ही अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी। वह अर्थव्यवस्था को दलदल से बाहर खींचने के उपायों का ब्योरा प्रदान करते हैं। राधिका कपूर 2018-2019 के श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों का विश्लेषण करती हैं। इसके द्वारा उन्होंने कार्यबल के उन वर्गों की पहचान की जो महामारी तथा लॉकडाउन के कारण होने वाले अव्यवस्थाओं का सबसे अधिक शिकार हुए हैं। एम. गोविंद राव ने मुद्दों के एक अनूठे समुच्चय का विश्लेषण किया। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए संसाधनों के जुड़ाव पर केंद्र द्वारा लिए गए आर्थिक नीतिगत निर्णयों की एक श्रृंखला में सामंतवाद की भावना के उल्लंघन को दर्शाया है। सी. पी. चंद्रशेखर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है।

खंड-7 में कोविड-19 के दौरान सामाजिक व्यवधानों पर चर्चा की गई। हनी ओबेरॉय वाहली इस बात की पड़ताल करते हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ जब वह लॉकडाउन में कई हफ्तों के लिए अपने घरों तक ही सीमित थे। नाओरेम पुष्पारानी चानू और गोर्की चक्रवर्ती ने अपने *मॉंगोलाइड फेनोटाइप* के कारण पूर्वोत्तर के नागरिकों की नस्लीय प्रोफाइलिंग और उन पर हमलों की चर्चा की है।

अंत में खंड-8 में भविष्य के साथ-साथ अतीत के विभिन्न पहलुओं की कोविड-19 के संदर्भ में जांच की है। रामप्रसाद सेनगुप्ता *होमोसेपियंस* के इतिहास में मानव-प्रकृति के कई संघर्षों का संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। वह बताते हैं कि संघर्ष और भी आक्रामक हो गए हैं और बढ़ती आवृत्ति के साथ

जूनोटिक वायरस के उद्भव के लिए भी अग्रणी हैं। इति इब्राहीम भविष्य को देखती हैं और चार समूहों के विचारकों की भविष्यवाणियों की बात करती हैं।

इन चार वैचारिक समूहों में राज्य के पक्षधर के प्रगतिशील आशावादी, वैश्वीकरण के अंत से जुड़े निराशावादी, आपदा-पूँजीवाद के निराशावादी, तथा तकनीकी आशावादी सम्मिलित हैं। अंत में, प्रेम चंद्रावरकर पूछते हैं कि हम कोविड-19 महामारी से क्या सबक सीख सकते हैं। क्या हम एक और मानवीय समाज तथा प्रकृति के साथ अधिक से अधिक सद्भाव का निर्माण कर सकते हैं?

पुस्तक वास्तव में व्यापक है, लेकिन अभी भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को बाहर छोड़ दिया गया है। पुस्तक वास्तव में प्रशंसा की हकदार है कि यह कोविड-19 के विभिन्न आयामों के विश्लेषण को एक सटीक और उपयोगी विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करती है।

यह पुस्तक चिकित्सा वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और किसी भी समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है।

मधु नागला

प्लॉट नम्बर 33

ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स

सेक्टर 9, रोहिणी

दिल्ली-110085

ई-मेल : bnagla@gmail.com